सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजिनियरिंग संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

पता :

इसरो स्टाफ आवास के सामने
जालहल्ली
बेंगलूरु – 560 013

फोन : 080-28385466 (निदेशक)
080-23457460
080-28385092
फैक्स: 080-28385093
ईमेल: 080-28385091
वेबसाईट: director@cicef.gov.in
cicef.gov.in

हम सोशल वेबसाइट पर हैं - हमें फ़ेसबुक पर फ़ॉलो करें https://twitter.com/CICEF_Bengaluru

https://facebook.com/cicef.bengaluru

संपादकीय सहायता

एन. के. पात्रा, उप निदेशक (अर्थशास्त्री)

जि. के. कुमार , कनिष्ठ अभियंता

संकलन एवं संपादन

एन. रवि शंकर

उप निदेशक (सिविल इंजिनियरिंग)

प्रकाशक:

एन. वेंकटेश प्रसाद

निदेशक

विषय सूची

पृष्ट सं

1.0 कें.म.त.इं.सं – अवलोकन....1
1.1 परिचय....1
1.2 संगठन....1
1.3 अधिदेश....3
1.3.1 मात्स्यिकी बंदरगाह....3
1.3.2 तटीय जलकृषि फार्म एवं हैचरी....4
2.0 संस्थान की उपलब्धियाँ....4
2.1 वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्धियाँ....5
2.1.1 इंजिनियरी एवं आर्थिक अन्वेषण....5
2.1.2 पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन....6
2.1.3 आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन....8
2.1.4 तकनीकी टिप्पणियाँ एवं मूल्यांकन....8
2.1.5 परियोजनाओं का मानिटरिंग एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण....10
3.0 सम्मेलन, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण....11
4.0 बैठकें....11
5.0 आगंतुक....12
6.0 प्रकाशन....12
7.0 प्रशासन एवं वित्त....12
7.1 बजट खर्च....12
7.2 पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/इस्तीफा....12
7.3 नियुक्तियाँ....12
7.4 एम ए सी पी योजना का कार्यान्वयन....13
7.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह....13
7.6 आयोजन....14
8.0 राजभाषा कार्यान्वयन / हिंदी शिक्षण योजना....14
9.0 पुस्तकालय....14
10.0 सूचना अधिकार (आरटीआई) का कार्यान्वयन....14
11.0 कर्मचारियों का कल्याण....14
12.0 तस्वीरें....15

प्रस्तावना

बेंगलूरु में स्थित केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजिनियरिंग संस्थान (कें.म.त.इं.सं), भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय मत्स्यपालन विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस संस्थान को देश के भीतर मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता के संबंध में अध्ययन करने एवं रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वार्षिक रिपोर्ट में संस्थान के प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध हैं।

इस वार्षिक रिपोर्ट में, वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान के महत्वपूर्ण क्रिया-कलाप और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है ।

1.0 कें.म.त.इं.सं- एक अवलोकन

1.1 परिचय

जनवरी 1968 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संस्थान (FAO/UN) के सहयोग के साथ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा संस्थान की स्थापना, मात्स्यिकी बंदरगाहों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण के रुप में हुई। भारत के समुद्री तट के योग्य स्थानों में मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए, इंजिनियरिंग एवं आर्थिक अन्वेषण करना, तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करना तथा यांत्रिक नौकाओं के लिए मात्स्यिकी बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध कराना आदि इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य थे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एव कृषि संगठन की सहायता समाप्त होने के पश्चात, जनवरी 1974 से लेकर दो साल तक की अवधि के लिए, संस्थान को स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (SIDA) से उपकरण एवं विशेषज्ञ परामर्श के रुप में तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। अगस्त 1983 में "केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजिनियरिंग संस्थान" के रुप में इसका पुनर्नामकरण किया गया। विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाने के पश्चात 1983 से लेकर संस्थान द्वारा उसकी परियोजनाओं के अंतर्गत, भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जल कृषि इंजिनियरिंग एवं खारा पानी झींगी फार्मों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। संस्थान को तटवर्ती जल संवर्धन झींगी फार्मो के विकास के लिए 1986 से 1991 तक UNDP/FAO से उपकरण तथा परामर्श के रुप में सहायता प्राप्त हुई।

1.2 संगठन

निदेशक संस्थान के प्रधान है और इस संस्थान के लिए स्वीकृत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या 47 है, इनमें तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारी शामिल है । पदों का ब्यौरा इस प्रकार है:

समूह	योजनेतर	
	तकनीकी	गैर-तकनीकी
क	10	-
ख (राजपत्रित)	03	01
ख (गैर राजपत्रित)	09	02
ग	07	15
कुल	**29**	**18**

संस्थान में इंजिनियरों एवं अर्थशास्त्रियों के सम्मिश्रित समूह कार्यरत है, जो मात्स्यिकी बंदरगाह और खारापानी झींगी फार्मों के विकास हेतु स्थान चुनने की दिशा में, अपेक्षित निवेश पूर्व अध्ययन करने, तकनीकी अर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना एवं अन्य सहायक

सुविधाओं के लिए विस्तृत निर्माण योजना बनाने में विशिष्ट ज्ञान और व्यापक अनुभव रखते है। मात्स्यिकी बंदरगाहों के लिए अन्वेन्षित स्थान एवं संस्थान की संगठन चार्ट नीचे दिए गए हैं ।

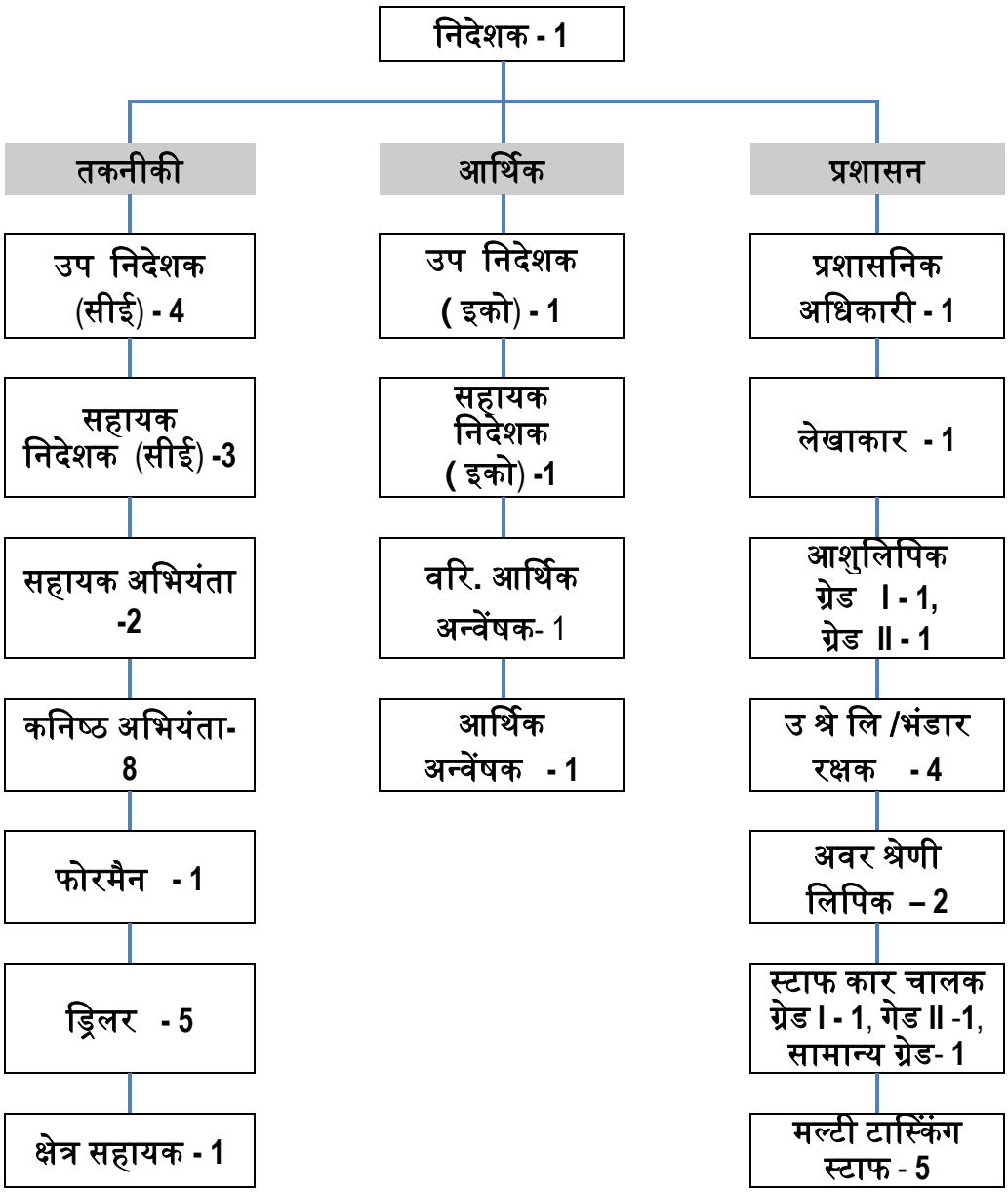

1.3 अधिदेश

मात्स्यिकी बंदरगाहों, तटीय जल कृषि फार्मों तथा हैचरियों के विकास के संबंध में इस संस्थान का अधिदेश इस प्रकार है:

1.3.1 मात्स्यिकी बंदरगाह

- मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए योग्य स्थान खोजने हेतु टोही सर्वेक्षण /साध्यता पूर्व अध्ययन करना तथा अनुवर्ती कार्य के रुप में विस्तृत इंजिनियरीग और आर्थिक अनुसंधान करना एवं तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।
- मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा पूरक सुविधाएं आदि के लिए प्रारंभिक निर्माण योजना तैयार करना।

- आवश्यकतानुसार मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों के विकास के लिए अपेक्षानुसार, तकनीकी एवं आर्थिक सलाह देना।
- मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सहयोग से, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन मात्स्यिकी बंदरगाहों की प्रगति का मानिटरिंग करना।

1.3.2 तटीय जल कृषि फार्म एवं हैचरी

- आर्थिक एवं इंजिनियरी अन्वेंषण करना, फार्मों के लिए उचित डिज़ाईन तैयार करना और तकनीकी-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।

2.0 संस्थान की उपलब्धियाँ

मार्च 2021 के अंत तक संस्थान ने मात्स्यिकी बंदरगाहों/ मछली उतारने के केंद्रों के विकास के लिए 104 स्थानों का अन्वेंषण किया और 121 (संसोधन सहित) स्थानों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

यूएनडीपी/ एफएओ की सहायता की अवधि के दौरान चार खारा पानी झींगा फार्म एवं झींगा बीज हैचरी विकसित किया गया। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त खारा पानी झींगी कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत, संस्थान द्वारा कुल 9,640 हेक्टर क्षेत्र के 13 स्थानों का सर्वेक्षण और उनका अव-मृदा परीक्षण किया गया। उनमें से 10 स्थानों के कुल 3,826 हेक्टर उत्पादक तालाब क्षेत्र के लिए संस्थान द्वारा तकनीकी आर्थिक रिपोर्ट तैयार की गई। पश्चिम बंगाल के दिघा, कैन्निंग एवं दिघिरपुर तथा आंध्र प्रदेश के भैरवपालम झींगी फार्मों में प्रायोगिक कृषि भी की गई।

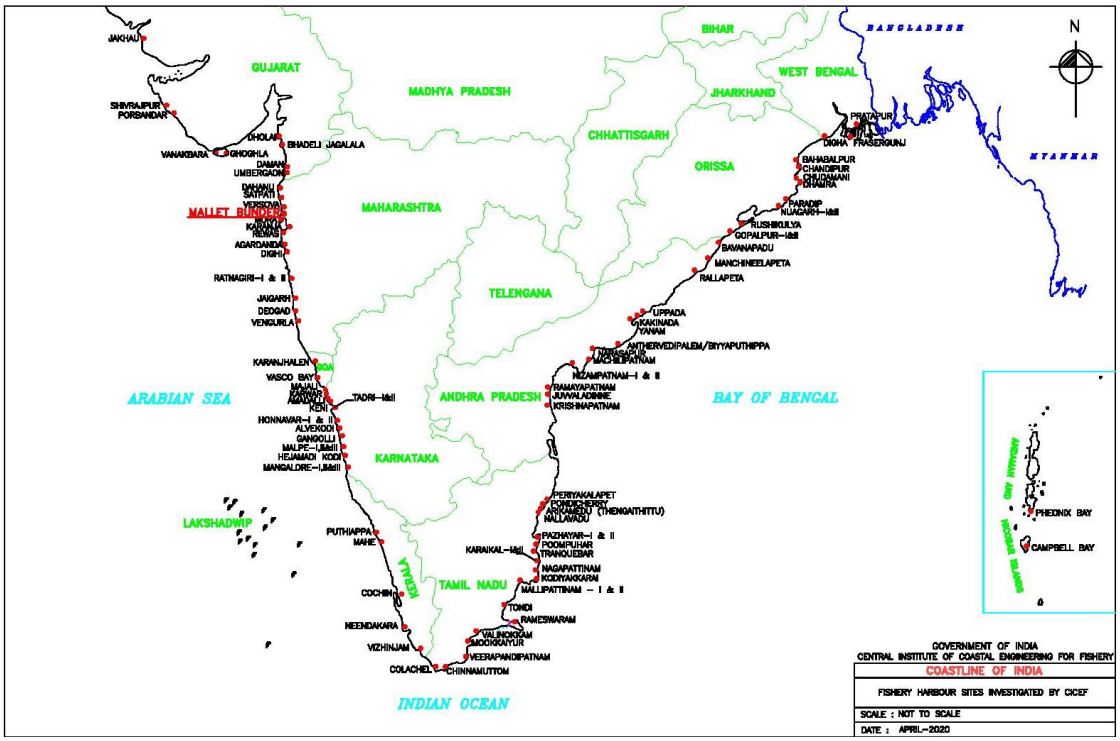

2.1 2020-21 के दौरान उपलब्धियाँ

2.1.1 इंजिनियरिंग एवं आर्थिक अन्वेषण

उड़ीशा के अस्तरंग (नुआगढ़) में मात्स्यिकी बंदरगाह फेज – II

- विस्तृत इंजिनियरी अन्वेंषण किया गया।
- ओडिशा एसओआर के अनुसार परियोजना की लागत रु. 82.86 करोड़ है और रिटर्न की आंतरिक दर (आईआरआर) की उपज 24.66% है।
- टीईएफआर मार्च, 2021 में जारी किया गया

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

नाव का आकार का डिजाइन

क्रमांक	नाव का आकार और प्रकार	संख्या
1.	9.0 m मोटर चालित नाव	1,628
2.	15.0 m ट्रलर	268
3.	12.0 m पर्स सिनर	64
	संपूर्ण	**1,960**

प्रस्तावित वाटरसाइड सुविधाएं

- एमएफवी के लिए आरसीसी पाइल्ड की
- मोटर चालित नाव के लिए समुद्र तट पर उतरने की सुविधा
- पत्थर की पिचिंग के साथ पुनर्मूल्यांकन
- आरसी स्लोपिंग हार्ड
- नौवहन सहायता

प्रस्तावित भू-भाग सुविधाएं

- भूमि के किनारे की सुविधाओं को रखने के लिए +3.60 मीटर का सुधार
- एमएफवी और मोटर चालित शिल्प के लिए नीलामी हॉल
- मछली लदान क्षेत्र
- आंतरिक सड़क नेटवर्क
- वाहन पार्किंग क्षेत्र
- बोट पार्किंग/मरम्मत यार्ड
- मात्स्यिकी प्रशासनिक कार्यालय
- मत्स्य पालन गियर शेड

- नेट मरम्मत शेड
- मछुआरे विश्राम शेड
- नाव मरम्मत की दुकान
- मछली व्यापारी छात्रावास
- रेस्टोरेंट
- सार्वजनिक शौचालय
- रेडियो संचार केंद्र
- ताजा पानी की आपूर्ति और वितरण प्रणाली
- जल निकासी, सीवरेज उपचार सुविधाओं, बिल्ज तेल विभाजक, खर्च किए गए तेल रिसेप्शन शेड, जहरीले अपशिष्ट संग्रह शेड, अपशिष्ट उपचार संयंत्र इत्यादि सहित ठोस, तरल और जहरीले अपशिष्ट निपटान प्रणालियों का प्रावधान
- विद्युत सबस्टेशन, हाई मास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइटिंग आदि सहित आंतरिक विद्युत आपूर्ति और वितरण प्रणाली
- मछली पालन बंदरगाह की सुरक्षा
- नागरिक सुविधा क्षेत्रों आदि में दुकानों/संबद्ध मत्स्य उद्योग के लिए बंदरगाह परिसर में खाली भूखंड
- हरियाली और भूनिर्माण
- अग्निशामक और
- मौजूदा सुविधाओं में सुधार

2.1.2 पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन

क) मात्स्यिकी बंदरगाह और मछली उतारने का केन्द्रों के विकास के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए महाराष्ट्र का रायगढ़ जिल्ले में फैले 17 स्थलों पर पूर्वनिर्धारितता अध्ययन (चरण -2) किया गया है।

जिला	साइट का नाम	सिफारिश की गयी
	एकदरा	मछली उतारने का केंद्र
	थेरोंदा	मछली उतारने का केंद्र
	वरसोली	मछली उतारने का केंद्र
	नवेदार-नवगाओं	मछली उतारने का केंद्र
	वशीनी-दादर	मछली उतारने का केंद्र
	केलवाने	मछली उतारने का केंद्र
	आवारे	मछली उतारने का केंद्र

रायगढ़	दिघोड़े	मछली उतारने का केंद्र
	सुरकिचपाड़ा	मछली उतारने का केंद्र
	डांडा	मछली उतारने का केंद्र
	मोरा	मछली उतारने का केंद्र
	हनुमान कोलीवाड़ा	मछली उतारने का केंद्र
	गावन	मछली उतारने का केंद्र
	न्हावा	मछली उतारने का केंद्र
	कोपार-शिवाजीनगर	मछली उतारने का केंद्र
	मोरावे	मछली उतारने का केंद्र
	उलवे-मोहे	मछली उतारने का केंद्र

ख) महाराष्ट्र का तीन जिल्ले यथा ठाणे, मुंबई सबरबन एवं पालघर जिल्ले में फैले 25 स्थलों पर पूर्वनिर्धारितता अध्ययन (चरण -2) किया गया है।

जिला	**साइट का नाम**
ठाणे	घनसोली
	भाटे बंदर
	देवतलाब
	उत्तानपाली
	डोंगरी लाडोबा
	आरएनपी पार्क कोलीवाड़ा
मुंबई सबरबन	वांद्रे (चिमबाइ)
	खार
	पटीलपाड़ा
	वारिनिपाड़ा
	मारवे
	एरंगलभाटी
	मनोरी

	गोराई
पालघर	दहानु
	उचेली-दांडी
	मुरबे
	सतपति
	तेंभी
	नाइगाओं
	अरनाला
	नवापुर
	रैनगाँव
	वसाई
	कोचिवाड़े

ग) मात्स्यिकी बंदरगाह और मछली उतारने का केन्द्रों के विकास के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह में फैले 3 स्थलों पर पूर्वनिर्धारितता अध्ययन किया गया है।

जिल्ले	**साइट का नाम**	**सिफारिश**
साउथ अंडमान	जंगलीघाट	मत्स्य बंदरगाह
मिडिल अंडमान	बेटापुर	सिफारिश नहीं की गई
	रंगत बे	सिफारिश नहीं की गई

2.1.3 आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट

- तामिलनाडु में विल्लीपुरम एवं काँचीपुरम जिले के कलुवेल्लि वॉटर मछली उतारने का केंद्र के लिए आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार और जारी की गयी।
- तामिलनाडु में कडलोर जिले के मुदासलोदाई और पोर्टोनोवो में मात्स्यिकी मछली उतारने का केंद्र के लिए आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार और जारी की गयी।
- उड़ीशा में बालासोर जिले के बहबलपुर में मछली बंदरगाह और भद्रक जिले के छुड़मनी मछली बंदरगाह के लिए आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार और जारी की गयी।

2.1.4 तकनीकी टिप्पणियाँ और मूल्यांकन

- एफआईडीएफ योजना के तहत तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में अरकोट्टुथुराई मत्स्य बंदरगाह की परियोजना लागत अनुमान की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत की गयी।

- एफआईडीएफ योजना के तहत तमिलनाडु के विल्लुपुरम और कांचीपुरम जिलों में काज़ुवेली जल मछली लैंडिंग केंद्र की परियोजना लागत अनुमान की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत की गयी ।
- एफआईडीएफ योजना के तहत तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगईपट्टिनम मत्स्य बंदरगाह पर अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत की गयी ।
- आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मंचीनेलापेटा फिश लैंडिंग सेंटर के निर्माण के लिए संरचनात्मक रेखाचित्रों की जांच की गई।
- पश्चिम बंगाल में 19 मत्स्य बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्र प्रस्तावों की परियोजना लागत अनुमान की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर मत्स्य बंदरगाह के लिए संशोधित लेआउट और टीईएफआर जारी किया गया।
- ओडिशा के बालासोर जिले में बहावलपुर मत्स्य बंदरगाह और भद्रक जिले में चुडामणि मछली पकड़ने के बंदरगाह के संशोधित परियोजना लागत अनुमानों की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- खुर्दा जिले में कालूपाड़ा और सोराना मछली लैंडिंग केंद्रों और ओडिशा के भद्रक जिले में कसिया मछली लैंडिंग केंद्र की परियोजना लागत अनुमान की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- पश्चिम बंगाल में नामखाना मात्स्यिकी बंदरगाह के परियोजना लागत अनुमान की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- पीएमएमएसवाई योजना के तहत केरल के कोच्चि जिले में थोप्पम्पडी मत्स्य बंदरगाह के परियोजना लागत अनुमान की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- एफआईडीएफ योजना के तहत केरल के अल्लापुझा जिले में अर्थुंगल मत्स्य बंदरगाह की परियोजना लागत अनुमान की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- एफआईडीएफ योजना के तहत गुजरात में वेरावल चरण-**II**, पोरबंदर चरण-**II**, माधवाड़, नवबंदर और सूत्रपाड़ा मात्स्यिकी बंदरगाह के परियोजना लागत अनुमानों की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- पीएमएमएसवाई के तहत महाराष्ट्र में निम्नलिखित 4 मत्स्य बंदरगाह और 20 मछली लैंडिंग केंद्रों के परियोजना प्रस्तावों की जांच की और एनएफडीबी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

जिला	**साइट का नाम**	**सिफारिश की गयी**
सिंधुदुर्ग	शिरोड़ा	मछली उतारने का केंद्र
	कारली	मछली उतारने का केंद्र
	देवली	मछली उतारने का केंद्र
	देवबाग	मछली उतारने का केंद्र

	दांडी मकेरबाग	मछली उतारने का केंद्र
	तारमुंब्री	मछली उतारने का केंद्र
रत्नागिरी	सखरीनाटे	मछली उतारने का केंद्र
	अमबोलगड़	मछली उतारने का केंद्र
	हेडवि हेडवातेड़	मछली उतारने का केंद्र
	बुधल	मछली उतारने का केंद्र
	पालशेत	मछली उतारने का केंद्र
	असगोली	मछली उतारने का केंद्र
	दाभोल	मछली उतारने का केंद्र
	हरनाई	मत्स्य बंदरगाह
	पज्पंधारी'	मछली उतारने का केंद्र
	अंजरले	मछली उतारने का केंद्र
	केलाशी	मछली उतारने का केंद्र
	वैशवी बाणकोट	मछली उतारने का केंद्र
रायगड़	जीवना	मत्स्य बंदरगाह
	भरडखोल	मत्स्य बंदरगाह
	आड़गाँव कोलीवाड़ा	मछली उतारने का केंद्र
	कोरलाई	मछली उतारने का केंद्र
	रेवदंडा	मछली उतारने का केंद्र
	आग्रव	मछली उतारने का केंद्र

2.1.5 परियोजना की निगरानी / चालू परियोजनाओं का तृतीय पक्ष निरीक्षण

- दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटक के उडुपी जिलों में चल रहे सभी मत्स्य संबंधी कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण।
- महाराष्ट्र में रायगढ़, ठाणे, मुंबई उपनगरीय और पालघर चार तटीय जिलों में फैले मछली लैंडिंग केंद्रों/मत्स्य पालन बंदरगाहों का पता लगाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में 42 मत्स्य स्थलों का दौरा किया।

- डमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण और मध्य अंडमान जिलों में फैले मछली लैंडिंग केंद्रों / मत्स्य बंदरगाहों का पता लगाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में 3 मत्स्य स्थलों का दौरा किया।

3.0 सम्मेलन, कार्यशाला और प्रशिक्षण

- अधिकारियों ने 3-4 नवंबर 2020 के दौरान सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे द्वारा आयोजित "तटीय क्षरण और सतत उपायों" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- 21 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में विश्व मत्स्य दिवस समारोह में वस्तुतः भाग लिया।

4.0 बैठकें

केंमतईसं के अधिकारीगण निम्नलिखित बैठकों भें उपस्थितत रहें :

- संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मात्स्यिकी विभाग की अध्यक्षता में 15 जून, 2020 को पीएमएमएसवाई दिशानिर्देश।
- 9 जून, 2020 को एनएफडीबी, समुद्री राज्यों और अन्य संस्थानों के प्रमुखों के अधिकारियों के साथ मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्य पालन) की अध्यक्षता में एफआईडीएफ परियोजनाएं।
- 23 जुलाई, 2020 को मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्य पालन) की अध्यक्षता में पीएमएमएसवाई दिशानिर्देश।
- 13 अगस्त, 2020 को एनएफडीबी, हैदराबाद के साथ एफआईडीएफ परियोजनाओं की 7वीं केंद्रीय शीर्ष निगरानी समिति (सीएएमसी) की बैठक।
- 29 अगस्त, 2020 को मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) की अध्यक्षता में **CICEF** गतिविधियाँ।
- 24 सितंबर, 2020 को संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्य पालन), मत्स्य विभाग और एनएफडीबी, हैदराबाद की अध्यक्षता में पीएमएसएसवाई के तहत परियोजनाओं की मंजूरी।
- 11 नवंबर, 2020 को सचिव (मत्स्य पालन), मत्स्य विभाग, नई दिल्ली, जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों, बंदरगाहों के प्रमुखों और संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ सागरमाला योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास।
- 18 नवंबर, 2020 को ईआईए समिति के सदस्यों और ओडिशा राज्य इंजीनियरों के साथ चांदीपुर मत्स्य बंदरगाह परियोजना पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) मंजूरी।
- संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मात्स्यिकी विभाग की अध्यक्षता में 17 दिसंबर, 2020 को सीआईएसएफ की गतिविधियों की समीक्षा।

- ओडिशा और महाराष्ट्र परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की एनएफडीबी, हैदराबाद और संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ 10 फरवरी, 2021 को बैठक।
- संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मात्स्यिकी विभाग की अध्यक्षता में 3 मार्च, 2021 को व्यय की स्थिति।

5.0 आगंतुक

मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और तटीय राज्यों/ संघशासित प्रदेशों के निम्नलिखित अधिकारियों ने विचार-विमर्श, बैठकों, तकनीकी मुद्दों पर चर्चा के लिए संस्थान का दौरा किया:

मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

- डॉ. च.सुवर्णा, आई.एफ.एस के साथ श्री अरुल बोस्को, कार्यकारी निदेशक, एनएफडीबी, हैदराबाद 19 फरवरी, 2021 को एनएफडीबी के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण पर चर्चा के लिए आए थे ।

तमिलनाडू सरकार

- एफआईडीएफ के तहत प्रस्तावित मात्स्यिकी बंदरगाह परियोजनाओं के विकास के संबंध में राज्य मत्स्य विभाग के अभियंताओं ने दौरा किया।

आंध्र प्रदेश सरकार

- आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मनचिनेलापेटा फिश लैंडिंग सेंटर के विकास के संबंध में राज्य मत्स्य विभाग के इंजीनियरों ने दौरा किया।

अन्य लोग

- मेसर्स पूजा एसोसिएट्स, पुणे, महाराष्ट्र मछली बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में दौरा किया।

6.0 प्रकाशन

- वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

7.0 प्रशासन एवं वित्त

7.1 प्रशासन एवं वित्त

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-योजना के तहत रु. 556.75 लाख रुपये के बजट अनुमान (बीई) और रु. 396.00 लाख रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) के जगह पर, रु. 380.36 लाख खर्च किए गए हैं।

7.2 पदोन्नति

- श्री सुरेशा, यू.डी.सी को दिनांक 01.04.2015 से लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया ।

7.3 सेवानिवृत्ति / प्रतिनियुक्ति / इस्तीफा

- श्री पी.एन. अच्युत प्रसाद, लेखाकार 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए।
- श्री दिनेश कुमार सोनी, वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषक, "भारत के महापंजीयक, जनगणना संचालन," उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति पर गए।
- श्री मनोज कुमार गुप्ता, अपर डिवीजन क्लर्क, 12 जून, 2020 को "गंगा बाढ़ नियंत्रण और कायाकल्प परियोजना", पटना में प्रतिनियुक्ति पर गए।

7.4 संशोधित आश्वासनित कैरियर प्रगति योजना (MACPS) का कार्यान्वयन

इस संस्थान के कर्मचारियों को एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान के मामलों पर विचार करने के लिए एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया।

समिति ने 12 जूलाई और 3 जानुयारी 2021 को अपनी बैठकें कीं, जिसमें वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए निम्नलिखित मामलों पर विचार किया और मंजूरी दी:

1. श्री शिवशंकर हेज, ड्रिलर
2. श्री जे राजेश, ड्रिलर

7.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), नई दिल्ली के निर्देश के अनुसरण में, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय के साथ मनाया गया है। सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं।

क) सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह अखंडता प्रतिज्ञा निदेशक, कें.म.त.इं.सं द्वारा दी गई।

ख) अधिकारियों और कर्मचारियों को वेबसाइट के माध्यम से सीवीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध अखंडता प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और प्रतिज्ञा लेने वालों को रिकॉर्ड करने की सलाह दी गई।

ग) सतर्कता जागरूकता सप्ताह का बैनर प्रवेश द्वार पर और कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरे सप्ताह के लिए प्रदर्शित किया गया।

घ) सतर्कता की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए भवन के भूतल पर एक नोटिस बोर्ड बनाया गया है ताकि सतर्कता गतिविधियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संचारों को प्रदर्शित किया जा सके।

ङ) "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" के विषय पर एक परशपर संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र को अधिकारियों ने जानकारीपूर्ण और लाभदायक पाया।

च) सभी अधिकारियों को सुशासन के मानकों से अवगत कराया गया।

7.6 आयोजन

- 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया ।
- 15 अगस्त, 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी, 2021 को 70वां गणतंत्र दिवस संस्थान में देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया।

8.0 राजभाषा कार्यान्व्यन / हिंदी शिक्षण योजना

- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न गतिविधियाँ की गईं।
- निम्नलिखित सदस्यों से युक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा शासकीय पत्र-व्यवहार में समय-समय पर हिंदी के प्रगतिशील उपयोग हेतु बैठक और समीक्षा की गई:

  सर्वश्री

एन वेंकटेश प्रसाद, निदेशक	अध्यक्ष
एन रवि शंकर ,उपनिदेशक (सीई)	सदस्य
एम बी बेल्लियप्पा, उपनिदेशक (सीई)	सदस्य
एन के पात्र उपनिदेशक (अर्थशास्त्र)	सदस्य

- संस्थान में दिनांक 14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस एवं दिनांक 14 से 25 सितंबर 20120 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

9.0 पुस्तकालय

- संस्थान के ग्रंथालय में तकनीकी एवं प्रशासन से संबंधित कई किताबें / जर्नल उपलब्ध हैं। इस वर्ष के दौरान 5 नई पुस्तकों को संग्रह में जोड़ा गया।

10.0 सूचना अधिकार(आरटीआई) का कार्यान्व्यन

- इस वर्ष के दौरान संस्थान को सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन 23 आवेदन प्राप्त हुएं और उनके लिए अपेक्षित सूचना दी गई।

11.0 कर्मचारियों का कल्याण

- श्री पी.एन. अच्युत प्रसाद, लेखाकार 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पर विदाई दी गई।

12.0 तस्वीरें

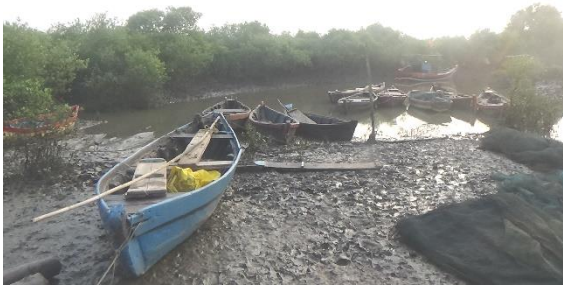

महाराष्ट्र में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन चरण -2

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन।